



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 1069) पटना, मंगलवार, 17 सितम्बर 2019

सं0 16/स्था0-01-01/2013-1097

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2019

विषय:- दिनांक 01.10.2019 के प्रभाव से भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी विशेष भू-अर्जन कार्यालयों को बंद कर निदेशक भू-अर्जन एवं पुनर्वास के एक पद को समाप्त करने तथा लंबित एवं नया भू-अर्जन कार्य संबंधित जिला के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा संपादित करने एवं इस निदेशालय अंतर्गत कुल 892 पदों में से 848 पदों एवं उस पर कार्यरत 179 कर्मियों की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपने तथा शेष 44 कर्मी प्रशासी विभाग में रखे जाने के संबंध में।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय वर्ष-1956 से कार्यरत है। विभागीय पत्रांक- 1401 दिनांक 19.06.1991 द्वारा विशेष भू-अर्जन कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकृत पदों का दिनांक 01.02.1991 से स्थायीकरण किया गया। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 1102 दिनांक 12.05.2016 द्वारा निदेशक भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय में विभिन्न पदों के निर्धारण

एवं पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निदेशालय के निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास का पद बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी का है। विशेष भू-अर्जन कार्यालयों के विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी का पद बिहार प्रशासनिक सेवा के उप-सचिव स्तर का है। पुनर्वास कार्यालय के पुनर्वास पदाधिकारी विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक अभियंता संवर्ग के पदाधिकारी होते हैं। वर्तमान में भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय के तहत कार्यरत 08 (आठ) विशेष भू-अर्जन कार्यालयों में आठ पदों के विरूद्ध अभी बिहार प्रशासनिक सेवा के मात्र चार पदाधिकारी कार्यरत हैं।

2. दिनांक 22.01.2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.04.2013 से भू-अर्जन का प्रस्ताव संबंधित जिले के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को प्रेषित किया जाय। जैस-जैसे विशेष भू-अर्जन कार्यालय का कार्य समाप्त होता जायेगा, वैसे-वैसे उन कार्यालयों को बन्द करने की कार्रवाई की जायेगी। विभागीय निदेश के तहत समय-समय पर नया भू-अर्जन का कार्य भी कार्यरत विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को सौंपा गया। बिहार रैयती लीज नीति, 2014 के तहत विभागीय भूमि प्राप्त करने के संबंध में भी कार्रवाई करने का दायित्व इन्हें दिया गया। भू-अर्जन के तहत 250 अभिलेखों में संबद्ध रकबा- 2561.65 एकड़ का अर्जन नये भू-अर्जन अधिनियम के तहत तथा कुल 314 अभिलेखों में संबद्ध रकबा 2618.907 एकड़ बिहार रैयती लीज नीति, 2014 के तहत प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इसकी अवधि क्रमशः दिनांक 31.03.2015, 31.03.2017 एवं 31.03.2019 तक विस्तारित की गई।

3. उक्त कंडिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर इन कार्यालयों के विघटन के संबंध में विभिन्न विभागों के बीच सैद्धांतिक सहमति बनाने हेतु दिनांक- 05.03.19 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत लंबित मामलों का संपादन संबंधित अधियाची पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक- 06.05.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में इस मामले पर निर्णय हेतु एक बैठक हुई। इस बैठक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 05.03.2019 की बैठक में लिए गए निर्णय को ही संपुष्ट किया गया। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2019 को आयोजित बैठक में माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, मुख्य सचिव, बिहार, विकास आयुक्त, बिहार, अपर मुख्य सचिव तथा अपर सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत भूमि अधिप्राप्ति की कार्रवाई विभागीय अधियाची पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता द्वारा ही किया जायेगा। इस हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को

समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी। विषय वस्तु से संबंधित अन्य कार्रवाई प्रशासी विभाग स्वयं करेगा।

4. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में दिनांक 01.10.2019 के प्रभाव से भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी विशेष भू-अर्जन कार्यालयों को बंद कर निदेशक भू-अर्जन एवं पुनर्वास के एक पद को समाप्त करने तथा लंबित एवं नया भू-अर्जन कार्य संबंधित जिला के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा संपादित करने एवं इस निदेशालय अंतर्गत कुल 892 पदों में से 848 पदों एवं उस पर कार्यरत 179 कर्मियों की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपने तथा शेष 44 कर्मी प्रशासी विभाग में रखे जाने का निर्णय लिया गया। **परिशिष्ट- 01**

5. यह आदेश दिनांक 01.10.2019 के प्रभाव से प्रभावी होगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को सूचनार्थ भेजी जाय।

अनुलग्नक:- परिशिष्ट।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सचिव।

(परिशिष्ट-1)

बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत कार्य हेतु जल संसाधन विभाग में पद सहित रखे जाने वाले तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपे जाने वाले स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची

क्रम सं०	पदनाम	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपने हेतु स्वीकृत पद	कुल कार्यरत बल	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपने हेतु कार्यरत बल	जल संसाधन विभाग में रखे जाने वाले पद सहित कार्यरत बल	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी	12	04	04	—	
02	लिपिक / टंकक	70	35	21	14	
03	लेखा लिपिक	12	00	—	—	
04	परिमापक / परिमापक-सह-प्रारूपकार / कानूनगो / प्रारूपकार	118	00	—	—	
05	मापक	165	33	18	15	
06	जीपचालक	12	00	—	—	
07	जंजीरवाहक	342	119	104	15	
08	आदेशपाल / दफ्तरी / आदेशिका चपरासी / कार्यालय चपरासी (कार्यालय परिचारी)	93	29	29	—	
09	कोषरक्षक	24	03	03	—	
	कुल:-	848	223	179	44	

नोट:-विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी के 12 पद एवं वर्ग-3 तथा 4 के कुल 880 पद स्वीकृत हैं।
संजीव हंस,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1069-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>